

डॉ. जी.बी. ग्रॉंट

बनाम

बिहार राज्य

30 मार्च, 1965

(के. सिजब्बा राव, सी. शाह और आर. एस. बछावत, न्यायमूर्ति गण)

मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, धारा 11, 18, और 30, और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, धारा 3 शामिल हैं। अपीलकर्ता के पास बिहार में कुछ भूमि थी, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। धारा 11 के तहत कलेक्टर ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, देय मुआवजा तय किया और मुआवजे को अपीलकर्ता और ग्राम समुदाय के सदस्यों के बीच बांट दिया, जिन्होंने भूमि के कुछ हिस्सों के लिए मुआवजे का दावा किया था। पुरस्कार धारा 12 के तहत दायर किया गया था। पुरस्कार से असंतुष्ट, अपीलकर्ता और ग्राम समुदाय के सदस्यों ने कलेक्टर से धारा 18 के तहत अदालत में संदर्भ बनाने के लिए कहा। हालाँकि, अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने से पहले, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 पारित किया गया था। इस अधिनियम के कारण अधिनियम की धारा 3 के प्रवर्तन से अपीलकर्ता की भूमि राज्य में निहित हो गयी।

राज्य ने तब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत कलेक्टर को अदालत का संदर्भ देने के लिए आवेदन किया, जिसमें दावा किया गया कि पुरस्कार के तहत मुआवजा राज्य को देय था क्योंकि उसने भूमि पर अपीलकर्ता का स्वामित्व हासिल कर लिया था। जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुआवजा राज्य को देय नहीं था। हालाँकि, अपील पर, उच्च न्यायालय ने राज्य के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि (1) कलेक्टर के पास धारा 11 के तहत मुआवजे की राशि आवंटित करने के बाद धारा 30 के तहत मामले को संदर्भित करने का कोई अधिकार

नहीं था; (2) चूंकि मुआवज़े का अधिकार पूरी तरह से पुरस्कार की तारीख से प्राप्त होता है, इसलिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना अपीलकर्ता को मुआवज़ा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं करती है; और (3) राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थ में 'रुचि रखने वाली व्यक्ति' नहीं थी, और धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं कर सकती थी।

न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

न्यायमूर्ति शाह और बच्चावत के अनुसार, (i) अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनके तहत कलेक्टर न्यायालय को संदर्भ दे सकता है, अर्थात् धारा 18 और धारा 30। दोनों धाराओं के तहत शक्तियां अलग-अलग हैं और आकस्मिकताओं में लागू की जा सकती हैं जो ओवरलैप नहीं होते। पुरस्कार के उस हिस्से में दिखाया गया व्यक्ति जो मुआवज़े के बंटवारे से संबंधित है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित है या जिस पर धारा 12(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, यदि वह पुरस्कार स्वीकार नहीं करता है, तो उसे आवेदन करना होगा। कलेक्टर को धारा 18 के तहत निर्धारित समय के भीतर मामले को न्यायालय में भेजना होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, यदि उसे दाखिल करने की सूचना नहीं दी गई है, तो वह विभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद उठा सकता है जिनके लिए यह देय है और संदर्भ के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। धारा 30 के तहत, मुआवज़े के उसके अधिकार के निर्धारण के लिए, जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है, या जो पुरस्कार के बाद से उसे हस्तांतरित हो सकता है। धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। [583 ई-584ए]

(ii) यह बनाने की शक्ति के प्रयोग पर आधारित नहीं है

धारा 30 के तहत संदर्भ है कि कलेक्टर ने अपने पुरस्कार से मुआवज़ा राशि का वितरण नहीं किया है।

बोरेगौड़ा और अन्य. वी. सुब्बाराమैया और अन्य, ए.आई.आर. (1959) मैसूर, 265, अस्वीकृत।

(iii) धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार मुआवजे के अधिकार का स्रोत नहीं है। एक पुरस्कार वास्तव में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा की गई पेशकश मात्र है; इच्छुक व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और सरकार धारा 48 के तहत अधिग्रहण वापस भी ले सकती है। यह केवल तभी होता है जब धारा 16 के तहत सरकार द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया हो, भूमि के मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए अपीलकर्ता का यह तर्क कि मुआवजे का शीर्षक पूरी तरह से पुरस्कार की तारीख से प्राप्त होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) धारा 31 के तहत पुरस्कार के तहत हकदार व्यक्ति को मुआवजा देने का सरकार का दायित्व यह नहीं है कि केवल वे व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है, वे धारा 30 के तहत विवाद उठा सकते हैं। एपी की योजना-

धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा किया गया बंटवारा केवल कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच निर्णायक होता है, न कि इच्छुक व्यक्तियों के बीच। पुरस्कार में हकदार घोषित किए गए व्यक्तियों को धारा 31 के तहत मुआवजे का भुगतान राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्ति दिलाता है, जिससे दावेदार के लिए धारा 30 के तहत या एक अलग संदर्भ में अपने अधिकार के लिए मुआवजे के लिए आंदोलन करना खुला रहता है। सुविधाजनक होना।

(v) बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर अपीलकर्ता का स्वामित्व राज्य में निहित हो गया और इसलिए अर्जित भूमि के मुआवजे का अधिकार राज्य को हस्तांतरित हो गया। इसके बाद राज्य सरकार और अपीलकर्ता के बीच "किस व्यक्ति को" मुआवजा देय था, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। राज्य को कलेक्टर के पुरस्कार की तारीख से पहले मौजूद स्वामित्व के तहत भूमि के लिए देय मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था और धारा 18 के अर्थ में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में इसके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जा सकता था। लेकिन अपीलकर्ता के बीच एक विवाद और राज्य के मुआवजे के पैसे पर उनके परस्पर विरोधी दावे स्पष्ट रूप से एक विवाद थे जिसे अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय में भेजा जा सकता था। धारा 30 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए विवाद के न्यायालय

के संदर्भ को बाहर करता है जिस पर पुरस्कार के बाद से भूमि के मालिक का अधिकार हस्तांतरित हो गया है।

*प्रोर्नोथा नाथ मित्रा बनाम राखल देस एडी, 11 कैल एल.जे. 420, संदर्भित।*

न्यायमूर्ति सुब्बा राव के अनुसार,-

(i) भूमि अधिग्रहण अधिकारी अधिनियम की धारा 30 के तहत मुआवजे के बंटवारे के मामले में कोई संदर्भ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके द्वारा धारा 11 के तहत मुआवजे को विभाजित करने का निर्णय दिया गया है और धारा 12 के तहत दायर किया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम पुरस्कार देने के मामले में एक सुव्यवस्थित योजना का खुलासा करता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी आपत्तियां मांगने के लिए नोटिस जारी करने के बाद धारा 11 में निर्धारित तीन मामलों पर निर्णय लेता है जो कि भूमि का वास्तविक क्षेत्र है। मुआवजे की राशि और मुआवजे का बंटवारा। बंटवारा करने से पहले वह निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक का सहारा ले सकता है:

(i) एक सहमत फॉर्मूले को स्वीकार करना;

(ii) स्वयं निर्णय लेना; और

(iii) यदि वह सोचता है कि निर्णय का निर्णय न्यायालय को संदर्भित करना है

कोर्ट जरूरी है। लेकिन एक बार जब पुरस्कार दे दिया जाता है, तो यह अंतिम हो जाता है और इसे केवल निर्धारित तरीके से यानी अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के माध्यम से फिर से खोला जा सकता है।

यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्त दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति जो अंतरण अंतरण द्वारा या ब्याज की दीवार के हस्तांतरण द्वारा पुरस्कार के बाद अधिकार प्राप्त करता है, वह अवशेष के बिना हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मांग कर सकता है

धारा 18 के तहत एक संदर्भ को न्यायालय में संदर्भ दिए जाने के बाद रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वह सिविल न्यायालय में जा सकता है

उन व्यक्तियों से मुआवज़ा वसूल करना जिन्होंने इसे उसके स्वामित्व के आधार पर प्राप्त किया था। दूसरी ओर विपरीत दृष्टिकोण असंगत स्थिति को जन्म देगा। यह लार्ड अधिग्रहण अधिकारी को अधिनियम की धारा 12 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत अंतिम पुरस्कार को फिर से खोलने में सक्षम बनाता है। यह उसे बिना किसी संदर्भ के संदर्भ देने में भी सक्षम बनाता है

परिसीमा की अवधि और इस प्रकार पुरस्कार द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए अधिकारों को बाधित करना।

सिविल, अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1964 की सिविल अपील संख्या 262 से 264 तक।

पटना उच्च न्यायालय के 5 जनवरी, 22 जनवरी, 1959 और 24 नवंबर, 1960 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील

1953 की मूल डिक्री संख्या 401 और 1954 की क्रमशः 297 और 298 की अपीलों में न्यायालय।

अपीलकर्ता की ओर से एस आर घोषाल और आर सी प्रसाद (सभी अपीलों में)।

डी. पी. सिंह, आर. के. गर्ग, एस.सी. अग्रवाल और एम.के. प्रत्यर्थी की ओर से राममूर्ति (सभी अपीलों में)।

न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने असहमतिपूर्ण राय दी। न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति बछावत का निर्णय शाह न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया

न्यायमूर्ति सुब्बा राव,

मुझे भाई जस्टिस शाह से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। अपीलों में उठाए गए प्रश्नों में से एक पर, अर्थात्, क्या भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12 के तहत पुरस्कार देने के बाद, अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा तय कर सकता है और उसे आपस में बांट सकता है। भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति, अधिनियम की धारा 30 के तहत बंटवारे के प्रश्न को न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करते हैं। न्यायमूर्ति शाह ने माना कि वह ऐसा कर सकते हैं; लेकिन, उनके प्रति बहुत सम्मान के साथ। एक अलग दृष्टिकोण अपनाओ.

न्यायमूर्ति शाह के फैसले में तथ्य पूरी तरह से बताए गए हैं और इसलिए उन्हें यहां दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।

उठाई गई समस्या का उत्तर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर तय किया जाना है। अधिनियम की धारा 9 कलेक्टर को आदेश देती है कि वह ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दे। यह कहते हुए कि सरकार भूमि पर कब्ज़ा करना चाहती है। और ऐसी भूमि में सभी हितों के मुआवजे का दावा उससे किया जा सकता है; उसके उप-धारा (2) के तहत ऐसे नोटिस में आवश्यक भूमि का विवरण बताया जाएगा और भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होने और उनकी प्रकृति बताने की आवश्यकता होगी। भूमि में संबंधित हित और ऐसे हितों के मुआवजे के लिए उनके दावों की राशि और विवरण, और धारा 8 के तहत किए गए माप पर उनकी आपत्तियां, यदि कोई हों।

धारा 11 के तहत, निर्धारित दिन पर या किसी अन्य दिन जिस पर जांच स्थगित कर दी गई है। कलेक्टर जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा और अपने अधीन एक पुरस्कार देगा (i) भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल; (ii) उनकी राय में ज़मीन के लिए मुआवज़ा दिया जाना चाहिए; और (iii) भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात या विश्वास वाले सभी व्यक्तियों के बीच उक्त मुआवजे का बंटवारा, जिनके बारे में, या जिनके दावों के बारे में उसे जानकारी थी, चाहे वे क्रमशः उसके सामने पेश हुए हों या नहीं। धारा 12 के तहत, "ऐसा पुरस्कार कलेक्टर के कार्यालय में दायर किया जाएगा और इसके बाद प्रदान किए गए को छोड़कर, कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा, चाहे वे क्रमशः कलेक्टर के सामने पेश हुए हों या नहीं। भूमि का वास्तविक क्षेत्र और मूल्य, और इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे का बंटवारा।" अनुभागों का समूह, एसएस 9 से 15, विषय वस्तु और कलेक्टर द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति का वर्णन करता है और उक्त विषय-वस्तु के संबंध में अंतिम पुरस्कार देने का प्रावधान करता है; एसएस 18 से 28 में न्यायालय के संदर्भ और उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 29 और 30 अधिनियम के भाग IV के अंतर्गत "मुआवजे का बंटवारा" शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। चूंकि निर्णय मुख्य रूप से इन प्रावधानों पर आधारित है, इसलिए इन्हें पूरा पढ़ना सुविधाजनक होगा।

धारा 29 प्रभाजन का विवरण निर्दिष्ट किया जाना है - जहां कई व्यक्ति रुचि रखते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति मुआवजे के प्रभाजन में सहमत हैं, तो ऐसे प्रभाजन का विवरण पुरस्कार में निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों के बीच पुरस्कार निर्णायक साक्ष्य होगा बंटवारे की शुद्धता के बारे में.

धारा 30 प्रभाजन के संबंध में विवाद - जब मुआवजे की राशि धारा 11 के तहत तय की गई है, यदि उसी या उसके किसी हिस्से के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है जिन्हें समान या उसका कोई हिस्सा देय है , कलेक्टर ऐसे विवाद को न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित कर सकता है।

जबकि धारा 11 कलेक्टर पर उसमें उल्लिखित तीन मामलों के संबंध में पूछताछ करने का वैधानिक कर्तव्य लगाती है, धारा 29 और

30 उक्त मामलों में से किसी एक के संबंध में विवाद का निर्णय करने के तरीके से निपटें, अर्थात्, निर्धारित मुआवजे का बंटवारा; धारा 29 के तहत। यदि दावेदार मुआवजे के बंटवारे में सहमत हैं, तो सहमत विवरण पुरस्कार में निर्दिष्ट किए जाएंगे और उक्त पुरस्कार उनके बीच अंतिम होगा।

यह स्पष्ट है कि यह समझौता आवश्यक रूप से पुरस्कार दिए जाने से पहले धारा 11 के तहत किए जाने वाले बंटवारे को संदर्भित करता है, क्योंकि अनुभाग में कहा गया है कि सहमत विवरण पुरस्कार में दर्ज किए जाएंगे। यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो एस 30 लागू होता है। यह मुआवजे का निपटान होने के बाद और बंटवारा किए जाने और पुरस्कार में शामिल किए जाने से पहले के चरण को भी संदर्भित करता है। यदि कोई सहमत फॉर्मूला नहीं था, तो भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास विवेकाधिकार है, संभवतः जब कोई जटिल प्रश्न हो, तो ए के संबंध में विवाद को न्यायालय में संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन अगर वह विवाद का फैसला खुद करना उचित समझता है तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम पुरस्कार देने के मामले में एक सुव्यवस्थित योजना को खारिज कर देता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आपत्तियां मांगने के लिए नोटिस जारी करने के बाद, धारा 11 में निर्धारित तीन मामलों पर निर्णय लेता है, अर्थात्, भूमि का वास्तविक क्षेत्र, मुआवजे की राशि मुआवजे के विभाजन के विपरीत। मुआवजे का बंटवारा करने से पहले वह निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक का सहारा ले सकता है: (एक सहमत फॉर्मूले को स्वीकार करना; (ii) स्वयं निर्णय लेना; और यदि उसे लगता है कि न्यायालय का निर्णय आवश्यक है तो न्यायालय का संदर्भ लेना लेकिन एक बार जब पुरस्कार दे दिया जाता है, तो यह अंतिम हो जाता है और इसे निर्धारित तरीके से ही दोबारा खोला जा सकता है। यानी, अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ के माध्यम से। यह निर्माण प्रावधानों के सुचारु संचालन के लिए बनाता है अधिनियम और किसी भी विसंगतियों को जन्म नहीं देता है, यह पीड़ित पक्षों के पुरस्कार को रद्द करने या संशोधित करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के अधिकार को भी प्रभावित नहीं करता है। जैसा भी मामला हो। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह दृष्टिकोण स्वीकार किया जाए, एक व्यक्ति जो पुरस्कार के बाद अंतर-विवो हस्तांतरण या ब्याज के हस्तांतरण द्वारा अधिकार प्राप्त करता है, वह बिना किसी उपचार के रहेगा। मुझे उस संबंध में कोई कठिनाई नहीं दिखती है। धारा 18 के तहत वह एक संदर्भ के लिए पूछ सकता है।

न्यायालय में संदर्भ भेजे जाने के बाद वह रिकॉर्ड पर लाए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। वह यह भी कर सकता है कि वह उन व्यक्तियों से मुआवज़ा वसूलने के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है जिन्होंने उसके स्वामित्व के आधार पर मुआवज़ा प्राप्त किया है।

दूसरी ओर, विपरीत दृष्टिकोण असंगत स्थिति को जन्म देगा। यह भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अधिनियम की धारा 12 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत अंतिम पुरस्कार को फिर से खोलने में सक्षम बनाता है। यह उसे बिना किसी सीमा अवधि के संदर्भ देने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार पुरस्कार द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए अधिकारों को परेशान करता है। इसलिए, मेरा मानना है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी मुआवजे के बंटवारे के मामले में अधिनियम की धारा 30 के तहत कोई संदर्भ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके द्वारा धारा 11 के तहत मुआवजे को विभाजित करने का निर्णय दिया गया है और उसकी धारा 12 के तहत दायर किया गया है।

बहस के दौरान यह सुझाव दिया गया कि चूंकि डॉ. ग्रांट का हित सरकार पर स्थानांतरित हो गया है, इसलिए यह माना जा सकता है कि धारा 18 के तहत किए गए संदर्भ में डॉ. ग्रांट के स्थान पर सरकार को वास्तव में रिकॉर्ड पर लाया गया था। जिला न्यायालय में अधिनियम. लेकिन कार्यवाही के किसी भी स्तर पर इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, वास्तव में डॉ. ग्रांट के स्थान पर सरकार को रिकॉर्ड पर लाने के लिए जिला न्यायालय में कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में प्रत्यार्थी को इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उक्त मुद्दा उठाने की अनुमति देना मेरे लिए उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप, मैंने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और जिला न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया। अपीलकर्ता को अपनी संपूर्ण लागत वहन करनी होगी।

शाह, जे. डॉ. ग्रेगर हग ग्रांट 'इसके बाद 'डॉ.' कहा जाएगा।

ग्रांट'-बिहार राज्य के संधाल परगना जिले में स्थित दुमका एस्टेट का मालिक था। 8 जून, 1949 को प्रकाशित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत एक अधिसूचना द्वारा, बिहार सरकार ने "कृषि" की स्थापना के लिए डॉ. ग्रांट की संपत्ति से भूमि के एक बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की।

फार्म।" कलेक्टर ने 25 मार्च, 1952 को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र को निर्धारित करते हुए, मुआवजा दिया, जो उनकी राय में भूमि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और सभी ज्ञात या इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे का बंटवारा किया गया। भूमि में। उसी दिन कलेक्टर के कार्यालय में पुरस्कार दायर किए गए थे। प्लॉट नंबर 142 के संबंध में, डॉ. ग्रांट और सदस्यों को समान शेयरों में मुआवजे के रूप में कलेक्टर द्वारा 575/14/- रुपये दिए गए थे। ग्राम समुदाय, जिसने मुआवजे के लिए दावा भी किया था। प्लॉट नंबर 68 के संबंध में, कलेक्टर ने मुआवजे के रूप में 294/6/- रुपये दिए। कई भूखंडों से युक्त 88.91 एकड़ क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में, कलेक्टर ने मुआवजे के रूप में 1,64,446/5/10 रुपये दिए और पुरस्कार में निर्धारित तरीके से बंटवारे का निर्देश दिया।

5 मई, 1952 को डॉ. ग्रांट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन दिया कि तीनों मामलों को मालिकों को भुगतान की गई मुआवजे की राशि के निर्धारण

के लिए न्यायालय द्वारा भेजा जाए। इसी तरह के आवेदन प्लॉट नंबर 68 के संबंध में भी दायर किए गए थे। एवं 142 ग्राम समुदाय के सदस्यों द्वारा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 30, 1950 की धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 22 मई, 1952 को दुमका एस्टेट बिहार राज्य में निहित हो गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार ने 21 अगस्त, 1952 को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। 15 अक्टूबर, 1952 को सरकारी वकील ने कलेक्टर के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें दावा किया गया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद से डॉ. ग्रांट को दी गई मुआवजा राशि राज्य सरकार को देय हो गई है, और डॉ. ग्रांट के बीच विवाद है। भुगतान के अधिकार के संबंध में अनुदान और राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय में भेजा जा सकता है।

कलेक्टर ने 5 नवंबर, 1952 को जिला न्यायालय, संधाल परगना को तीन संदर्भ दिए, उनमें से दो संदर्भ भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 और 18 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तीसरा धारा 30 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे। न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1954 द्वारा माना कि जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12 के तहत कलेक्टर के समक्ष पुरस्कार दायर किया गया था, तो बिहार राज्य को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और राज्य इस पर कोई दावा नहीं कर सकता था। मुआवजा राशि प्रदान की गई। जिला न्यायाधीश ने डॉ. ग्रांट और ग्राम समुदाय के बीच मुआवजे के बंटवारे को बरकरार रखा और भूमि का मूल्यांकन बढ़ाया और निर्देश दिया कि बढ़ी हुई दर पर मुआवजा दिया जाए।

संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, राज्य द्वारा तीन ए अपील संख्या 401/1953, 297/1954 और 298/298 को उच्च न्यायालय, पटना में प्राथमिकता दी गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के मालिक का स्वामित्व उस अधिनियम के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा नहीं ले लिया जाता है, और चूंकि अधिग्रहित भूमि में डॉ. ग्रांट का शीर्षक कायम है बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर वैधानिक रूप से राज्य में निहित होने के कारण, वह मुआवजा राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय की

राय में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा कब्जा प्राप्त करने से पहले मुआवजे की धनराशि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित था, और किसी विवाद पर यह कलेक्टर के लिए खुला था। मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकार के बारे में राज्य द्वारा, अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय को एक संदर्भ बनाने के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ, इन तीन अपीलों को डॉ. ग्रांट द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

अपील के समर्थन में तीन तर्क दिए गए हैं: (1) कलेक्टर के पास धारा 11 (2) के तहत मुआवजे की राशि को विभाजित करने के बाद धारा 30 के तहत मामले को संदर्भित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मुआवजे का अधिकार पूरी तरह से प्राप्त होता है। और पुरस्कार की तिथि पर, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना ने डॉ. ग्रांट को मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया, और (3) राज्य सरकार "हितबद्ध व्यक्ति" नहीं थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत, और धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी होने के बाद, उपयुक्त सरकार धारा 7 से 16 में निर्धारित तरीके से अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। धारा 9 मुआवजे के लिए भूमि के क्षेत्र की जांच का प्रावधान करती है। जो देय है और मुआवजे का बंटवारा है।

धारा 11 के तहत कलेक्टर को भूमि का वास्तविक क्षेत्र, मुआवजा, जो उनकी राय में, भूमि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, और उक्त मुआवजे को ज्ञात या माने जाने वाले सभी व्यक्तियों के बीच बांटने के लिए एक पुरस्कार देने के लिए अधिकृत है। भूमि में रुचि रखने वाले, या जिनके दावों के बारे में उसके पास जानकारी है, भले ही वे क्रमशः उसके सामने पेश हुए हों या नहीं। जब कलेक्टर के कार्यालय में पुरस्कार दाखिल किया जाता है तो यह कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक साक्ष्य बन जाता है, भले ही वे क्रमशः कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, भूमि के वास्तविक क्षेत्र और मूल्य और बंटवारे के बारे में इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे का। जब धारा 16 के तहत कलेक्टर द्वारा कब्जा ले लिया जाता है तो भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित हो जाती है, सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है। धारा 17 के द्वारा कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया जाता है, जब तत्काल मामलों में उपयुक्त सरकार अपशिष्ट या कचरे पर कब्जा करने का निर्देश देती है। पुरस्कार देने से पहले ही कृषि योग्य भूमि। धारा 48

सरकार को ऐसी किसी भी भूमि का अधिग्रहण वापस लेने का अधिकार देती है जिस पर कब्ज़ा नहीं लिया गया है।

धारा 18 के द्वारा कलेक्टर को भूमि की माप, मुआवजे की राशि के संबंध में आपत्तियों, निर्धारण के लिए जिला न्यायालय को संदर्भित करने का आदेश दिया गया है। जिन व्यक्तियों को यह देय है, या इच्छुक व्यक्तियों के बीच उसका बंटवारा। भाग IV मुआवजे के बंटवारे से संबंधित है। यदि हितबद्ध व्यक्ति मुआवजे के बंटवारे में सहमत हैं, तो विवरण

ऐसे प्रभाजन को पुरस्कार (धारा 29) में निर्दिष्ट किया जाएगा: यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो कलेक्टर, यदि मुआवजे या उसके किसी हिस्से के प्रभाजन या उन व्यक्तियों के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिन्हें समान या यदि उसका कोई भाग देय है, तो ऐसे विवाद को धारा 30 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय के लिए देखें। अधिनियम का भाग V जिसमें एसएस 31 से 34 शामिल है, भुगतान से संबंधित है

मुआवज़ा। धारा 31 के तहत कलेक्टर को उसके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान पुरस्कार के अनुसार उसके हकदार इच्छुक व्यक्तियों को करना होगा। धारा 31 की उप-धारा (2) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का दायित्व, जो अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे का पूरा या कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकता है, उसे कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को भुगतान करना होगा। प्रभावित। धारा 32 और 33 भूमि हस्तांतरित करने में अक्षम व्यक्तियों की भूमि के संबंध में और अन्य मामलों में जमा किए गए धन के निवेश से संबंधित हैं, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है।

धारा 34 कलेक्टर को प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है यदि भूमि पर कब्ज़ा लेने के समय से लेकर भुगतान या जमा होने तक मुआवजा का भुगतान या जमा नहीं किया जाता है।

दो प्रावधान एसएस 18(1) और 30 हैं जो कलेक्टर को मुआवजे के बंटवारे या जिन व्यक्तियों को यह देय है, के विवाद को न्यायालय में संदर्भित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। धारा 18 की

उप-धारा (1) द्वारा कलेक्टर को उस धारा की उप-धारा (2) द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवेदन पर बंटवारे, या मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार के विवाद को संदर्भित करने का आदेश दिया गया है। इच्छुक व्यक्ति जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है। धारा 30 कलेक्टर को धारा 11 के तहत मुआवजे का निपटारा होने के बाद न्यायालय को संदर्भित करने के लिए अधिकृत करती है, उसी या उसके किसी हिस्से के विभाजन या उन व्यक्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को जिनके लिए समान है

या उसका कोई भाग देय है।

पुरस्कार के उस हिस्से में दिखाया गया व्यक्ति जो मुआवजे के बंटवारे से संबंधित है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होता है, या जिस पर धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस दिया जाता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है पुरस्कार स्वीकार करें, मामले को न्यायालय में भेजने के लिए धारा 18(2) के तहत निर्धारित समय के भीतर कलेक्टर को आवेदन करें। लेकिन एक व्यक्ति जो कलेक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, यदि उसे फाइलिंग की सूचना नहीं दी गई है, तो वह प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद उठा सकता है, जिन्हें यह देय है, और इसके लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। मुआवजे के उसके अधिकार के निर्धारण के लिए धारा 30 के तहत एक संदर्भ, जो पुरस्कार से पहले मौजूद हो सकता है, या जो पुरस्कार के बाद से उसे हस्तांतरित हो सकता है।

जबकि धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन उप-धारा (2) सीएल (बी) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, धारा 30 के तहत ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। फिर धारा 18 के तहत कलेक्टर को भेजा जाता है रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका पर एक संदर्भ बनाएं। धारा 30 के तहत कलेक्टर को संदर्भ देने का आदेश नहीं दिया गया है: वह विवाद उठाने वाले व्यक्ति को बंटवारे के संबंध में, या उस व्यक्ति को, जिसे मुआवजा देय है, विवाद को एक मुकदमे में उठाने और मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है। उनके द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया।

हम बोरेगौड़ा और एक अन्य बनाम सुभारामैया और ऑयलर्स मामले में मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यदि कलेक्टर ने अपने पुरस्कार से मुआवजा राशि का बंटवारा कर लिया है तो धारा 30 के तहत विवाद को संदर्भित करने की उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 11 का खंड (iii) कलेक्टर को भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात या विश्वास वाले व्यक्तियों के बीच मुआवजा राशि बांटने का आदेश देता है: उसके पास इस मामले में कोई विवेक नहीं है। विभाजन से संबंधित विवाद को या जिन व्यक्तियों को यह देय है, उन्हें संदर्भित करने के लिए धारा 30 के तहत शक्ति का प्रयोग, यह सच है, विवेकाधीन है: कलेक्टर कर सकता है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यह उस शक्ति के प्रयोग पर आधारित नहीं है कि कलेक्टर ने अपने पुरस्कार द्वारा मुआवजे की राशि को विभाजित नहीं किया है।

हम मैसूर उच्च न्यायालय से भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत शक्ति का प्रयोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18(2) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक प्रस्ताव पर किया जाना चाहिए। हमारे निर्णय में कलेक्टर द्वारा धारा 18(1) और धारा 30 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ अलग-अलग हैं और उन आकस्मिकताओं में लागू की जा सकती हैं जो ओवरलैप नहीं होती हैं।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर डॉ. ग्रांट का अधिकार बिहार राज्य में निहित हो गया। 25 मार्च, 1952 को जब कलेक्टर ने धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया, तो पुरस्कार में रुचि रखने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉ. ग्रांट और ग्राम समुदाय के सदस्य थे, लेकिन अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि में डॉ. ग्रांट का शीर्षक कायम था, बिहार भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन द्वारा 22 मई, 1952 से बिहार राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। तब राज्य सरकार और डॉ. ग्रांट के बीच "किस व्यक्ति को" मुआवज़ा देय था, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया।

राज्य को कलेक्टर के पुरस्कार की तारीख से पहले मौजूद शीर्षक के तहत भूमि के लिए देय मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था, और राज्य द्वारा संदर्भ के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा

सकता था। धारा 18(1) के अर्थ में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में। मुआवजा प्राप्त करने का राज्य का अधिकार तभी उत्पन्न हुआ जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना के परिणामस्वरूप, संपत्ति के लिए डॉ. ग्रांट का स्वामित्व वापस ले लिया गया।

कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को दी गई एक पेशकश है: बाद वाला प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। वह पर्याप्त मुआवजे के लिए अपने दावे के निर्णय के लिए न्यायालय का संदर्भ मांग सकता है। इच्छुक व्यक्ति संदर्भ के लिए सहायता राशि की पर्याप्तता के विरोध में मुआवजा भी स्वीकार कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्णय दिए जाने के बाद भी, लेकिन कब्जा लेने से पहले, सरकार किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए भी खुली है। इसलिए यह कलेक्टर का पुरस्कार नहीं है जो मुआवजे के अधिकार का स्रोत है: पुरस्कार उपयुक्त सरकार की पेशकश की मात्रा निर्धारित करता है, जो इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार ने मालिक की भूमि को अपने अधीन ले लिया है, या लेने का इरादा रखती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार। सेरजू प्रसाद साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य['] में इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की योजना पर विचार करते समय यह देखा गया कि जब सरकार किसी पुरस्कार के बाद भूमि पर कब्जा कर लेती है तो भूमि के मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है। का मुआवजा बनता है। यह अधिनियम की योजना द्वारा भी समर्थित है। न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की अतिरिक्त राशि पर कलेक्टर द्वारा कब्जा लेने की तारीख से धारा 28 के तहत ब्याज देय है। इसी प्रकार धारा 34 के तहत मुआवजे पर कब्जा लेने की तारीख से ब्याज देय होता है, यदि भूमि पर कब्जा लेने से पहले या उससे पहले भुगतान नहीं किया जाता है या जमा नहीं किया जाता है।

बिहार राज्य का अधिकार 22 मई, 1952 को उत्पन्न हुआ जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर भूमि का स्वामित्व इसमें निहित हो गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कलेक्टर को उस व्यक्ति के स्वामित्व के निर्धारण के लिए धारा 30 के तहत एक संदर्भ बनाने से रोकता है जिसने पुरस्कार की तारीख से मुआवजे का अधिकार हासिल कर लिया है। यदि न्यायालय में संदर्भ भेजे जाने के बाद, व्यक्ति का हित समाप्त हो जाता है या उसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को विरासत, उत्तराधिकार, दिवालियापन, ज़ब्त, वैधानिक हस्तांतरण के अन्य रूपों के अनिवार्य समापन के कारण हस्तांतरित हो जाता है,

तो यह पार्टी के लिए खुला होगा। जिसे शीर्षक उस दावे पर मुकदमा चलाने के लिए हस्तांतरित किया गया है जिस व्यक्ति से शीर्षक हस्तांतरित किया गया है वह मुकदमा चला सकता था।

प्रोमोथा नाथ मित्रा बनाम राखल दास एडी (2) में यह माना गया था कि भूमि के मालिक के कहने पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ पर पुरस्कार के बाद उसके अधिकारों के खरीदार द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। राजस्व नीलामी में, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी संदर्भ पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है जिस पर संबंधित व्यक्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि मुआवजे के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी विवाद के संदर्भ का दावा करने का अधिकार उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिस पर पुरस्कार की तारीख से शीर्षक हस्तांतरित हो गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना यह है कि मुआवजे की मात्रा के बारे में सभी विवादों का निर्णय अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेकर किया जाना चाहिए; इसका यह भी इरादा है कि मालिकों के मुआवजे के अधिकारों के बारे में विवादों का निर्णय मुख्य विवाद से संबंधित उस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए जिसे शक्ति सौंपी गई है। इस संबंध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बंटवारे के कारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के विवादों के न्यायनिर्णयन तक विस्तारित है जो मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं, और धारा 30 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उठाए गए विवाद के न्यायालय के संदर्भ को बाहर करता है। उस व्यक्ति द्वारा जिस पर पुरस्कार के बाद से भूमि के मालिक का अधिकार हस्तांतरित हो गया है।

इस बात पर जोर दिया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31 के तहत कलेक्टर पुरस्कार के अनुसार हकदार व्यक्तियों को उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है और इसमें निहित है कि मुआवजे की राशि में एक अधिकार उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति जिसे पुरस्कार के तहत मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, और इसलिए केवल वही व्यक्ति धारा 30 के तहत विवाद उठा सकते हैं जिनके नाम पुरस्कार में निर्धारित हैं। यह विवाद धारा 30 की स्पष्ट शर्तों द्वारा खारिज कर दिया गया है। कलेक्टर मुआवजे की राशि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के परस्पर विरोधी अधिकारों को अंतिम रूप से तय करने के लिए अधिकृत नहीं है: वह मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। प्रस्तावित मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, यह सच है कि उसे मुआवजे की राशि को भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात

या विश्वास वाले व्यक्तियों के बीच बांटना होगा, जिनके बारे में, या जिनके दावों के बारे में उसे जानकारी है, चाहे या वे उसके सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। लेकिन कलेक्टर द्वारा बंटवारे की योजना अंततः मुआवजे की राशि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करती है: पुरस्कार केवल कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच निर्णायक होता है, न कि इच्छुक व्यक्तियों के बीच। कलेक्टर के पास मुआवजे के अधिकार पर अंतिम निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, उस विवाद का निर्णय या तो धारा 18 के तहत या धारा 30 के तहत या एक अलग मुकदमे में किया जाना चाहिए। इसलिए धारा 31 के तहत उस व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान, जिसे पुरस्कार द्वारा उसका हकदार घोषित किया गया है, राज्य को मुआवजा देने के अपने दायित्व से मुक्त कर देता है (न्यायालय द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन), जिससे मुआवजे के दावेदार के लिए अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना खुला हो जाता है। धारा 30 के तहत एक संदर्भ या एक अलग मुकदमे द्वारा।

बिहार राज्य और डॉ. ग्रांट के बीच विवाद को स्पष्ट रूप से कलेक्टर द्वारा निर्णय के लिए न्यायालय में भेजा गया है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत, अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर डॉ. ग्रांट का स्वामित्व राज्य में निहित हो गया, और इसलिए अर्जित भूमि के मुआवजे का अधिकार राज्य को हस्तांतरित हो गया। डॉ. ग्रांट और राज्य के बीच मुआवजे की रकम पर उनके परस्पर विरोधी दावों का विवाद स्पष्ट रूप से एक विवाद था जिसे वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत न्यायालय में भेज सकते थे और वास्तव में इसे न्यायालय में भेजा गया था। हम डॉ. ग्रांट के वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि कलेक्टर द्वारा धारा 30 के तहत दिया गया संदर्भ अक्षम था क्योंकि जिस तारीख को पुरस्कार दिया गया था उस दिन राज्य को मुआवजे की राशि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब पुरस्कार दिया गया तो बिहार राज्य का अधिकार निस्संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन एक बार जब उपाधि जो मूल रूप से डॉ. ग्रांट में निहित थी, वैधानिक रूप से राज्य को हस्तांतरित हो गई, तो राज्य के लिए संदर्भ का दावा करना खुला था, इसलिए नहीं कि

राज्य उस तारीख से पहले मुआवजे की रकम में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति था। पुरस्कार का, लेकिन उस अधिकार के कारण जो पुरस्कार बनने के बाद से उत्पन्न हुआ है।

इसलिए हम लागत सहित अपीलों को खारिज करते हैं। एक सुनवाई शुल्क होगा।

आदेश

बहुमत के फैसले के बाद, अपीलें लागत सहित खारिज कर दी जाती हैं। एक सुनवाई शुल्क होगा।

डॉ. जी.बी. ग्रांट बनाम बिहार राज्य

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।